

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 450/2025

नीलेश्रमचन्दानी एवं 2 अन्य

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : निपुन सिंह, राजर्षि गुप्ता, सुधांशु कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : अनिकेत गुप्ता, जी.ए., शिवम शुक्ला, सुचिता मेहरोत्रा

न्यायालय संख्या - 42

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद

1. याचिकाकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजर्षि गुप्ता, राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री अमित सिन्हा और सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवम शुक्ला और श्री अनिकेत गुप्ता को सुना।

2. यह रिट याचिका भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 352, 351(2), 69 के तहत 2024 के प्रकरण अपराध संख्या 566 के रूप में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 (इसके बाद बी.एन.एस. के रूप में संदर्भित), पुलिस स्टेशन सेक्टर 63, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर के तहत दायर की गई है, और प्रत्यर्थी

अधिकारियों को आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में याचिकाकर्तागण को गिरफ्तार न करने का निर्देश देने के लिए दायर की गई है।

3. प्रारंभ में 12.12.2024 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें बी.एन.एस. की धारा 352, 351(2) और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 (इसके बाद डी.पी. अधिनियम)। यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता संख्या 1, नीलेश रामचंदानी, पहले सूचनाकर्ता को जानते थे और जून, 2023 के महीने में एक सगाई समारोह आयोजित करके विवाह गठबंधन में प्रवेश किया था। शादी 12.11.2024 को होनी थी। शादी होने से पहले, 04.11.2024 को, प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता संख्या 1 के पिता, जिन्हें भी आरोपी बनाया गया था और याचिकाकर्ता संख्या 2 के रूप में पेश किया गया था, ने इलाहाबाद में 50 लाख रुपये नकद, एक फॉर्च्यूनर कार और एक फ्लैट की मांग की थी। जब प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, यह मांग सूचनाकर्ता के पिता द्वारा पूरी नहीं की गई, तो याचिकाकर्ता संख्या 1 के पिता ने पहले सूचनाकर्ता के पिता के साथ दुर्व्यवहार किया और कहा कि वह अपने बेटे की शादी एक ऐसे परिवार में कर देगा जो उसकी मांगों को पूरा करेगा। मुख्य आरोप से पहले, एक विवरण दिया गया था कि पहले सूचनाकर्ता को याचिकाकर्ता संख्या 1 के बारे में कैसे पता चला। प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही कहा गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 4 ने बीए एलएलबी करने के बाद, एलएलएम करने के उद्देश्य से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर में दाखिला लिया था। इसके अलावा याचिकाकर्ता संख्या 1 ने एलएलएम कोर्स करने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर में दाखिला लिया। दोनों ने वर्ष 2020 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर में दाखिला लिया था। एलएलबी कोर्स करते हुए भी दोनों ने लखनऊ में पढ़ाई की थी और भले ही वे एक-दूसरे को जानते थे, लेकिन वे बहुत करीब नहीं थे। हालाँकि, चूंकि याचिकाकर्ता संख्या 1 प्रत्यर्थी संख्या 4 को पहले से जानता था और चूंकि उसने दोस्ती का अनुरोध किया था, इसलिए वे दोनों बात करते रहे। प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही यह कहा गया था कि जब दोनों ने अपना एलएलएम कोर्स पास किया था, तो प्रत्यर्थी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता संख्या 1 को भी सूचित किया था कि वह पिछड़ी जाति की है। हालाँकि, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अपनी पहले की प्रतिबद्धता को जारी रखा था कि वह प्रत्यर्थी संख्या 4 को पसंद करता है और वह उसके साथ शादी के संबंध में अपने परिवार से बात करेगा। उसने उसे यह भी मना लिया था कि वह उससे शादी करेगा और किसी और से नहीं। उस समय, प्रत्यर्थी संख्या 4 के पिता नोएडा में बिजली विभाग में नौकरी कर रहे थे और वहां याचिकाकर्ता उनसे मिलने भी गए थे। जब याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 4 के पिता से मिलने गए

थे, तब प्रत्यर्थी संख्या 4 के चाचा अर्थात् श्री हरस्वरूप (मामा) भी मौजूद थे। प्रत्यर्थी संख्या 4 के माता-पिता शादी के लिए सहमत हो गए थे। हालांकि, शादी तुरंत संपन्न नहीं हुई थी, लेकिन दो साल बाद होनी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा था और प्रत्यर्थी संख्या 4 न्यायिक सेवाओं की तैयारी कर रहा था।

4. मुकदमा अपराध संख्या 566/2024 के रूप में दर्ज दिनांक 12.12.2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए तत्काल रिट याचिका दायर की गई थी। हालांकि, शुरू में इस प्रकरण को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2025 को मध्यस्थता और सुलह केंद्र, इलाहाबाद को भेज दिया गया था ताकि दोनों पक्षों के बीच सुलह हो सके। जबकि प्रकरण को मध्यस्थता केंद्र द्वारा देखा जा रहा था, विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना जारी थी। दिनांक 09.04.2025 को जब मध्यस्थता विफल हो गई, तो प्रकरण एक बार फिर इस न्यायालय के समक्ष आया। दिनांक 28.04.2025 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

सन्दर्भ: सिविल प्रकीर्ण संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 3/2025

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री राजर्षि गुप्ता, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता सुश्री सुचिता मेहरोत्रा और राज्य के लिए विद्वान एजीए को सुना।
2. संशोधन आवेदन की अनुमति है, संशोधन को तुरंत किया जाए।
3. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, यदि कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित अगली तारीख को या उससे पहले जवाबी हलफनामा दायर कर सकते हैं।

सन्दर्भ: रिट याचिका

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री राजर्षि गुप्ता, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता सुश्री सुचिता मेहरोत्रा और राज्य के लिए विद्वान एजीए को सुना।
2. इस याचिका में मांगी गई राहत दिनांक 12.12.2024 को 2024 के मुकदमा अपराध संख्या 566 के रूप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए है, जो धारा 352, 351(2), बीएनएस, 2023 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4, पुलिस स्टेशन सेक्टर 63, जिला गौतमबुद्ध नगर के तहत दर्ज है। आगे अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त प्रकरण में याचिकाकर्तागण को गिरफ्तार न किया जाए।

3. इस न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 15.1.2025 के आदेश के माध्यम से प्रकरण को इस न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह केंद्र को भेज दिया है और रिपोर्ट के अनुसार, पक्ष प्रकरण को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं कर सके। अंत में, हम प्रकरण को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए पक्षकारों को एक और अनुमति देने के इच्छुक थे।

4. आज, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता सुचिता मेहरोत्रा ने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरण को निपटाने की शायद ही कोई संभावना है, हालांकि पहले यह विफल रहा था।

4. श्री परितोष मालवीय ने कहा कि इस प्रकरण को दिनांक 15.1.2025 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह केंद्र को भेजा गया था। वह निष्पक्ष रूप से कहते हैं कि एक बार जब प्रकरण को मध्यस्थता और सुलह केंद्र को भेज दिया गया था, तो निश्चित रूप से विवेचना बहुत धीमी गति से होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चल रही विवेचना की वर्तमान स्थिति को रिकॉर्ड पर रखने के लिए उन्हें कुछ और समय दिया जा सकता है।

5. उनके अनुरोध पर प्रकरण स्थगित किया जाता है।

6. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री राजर्षि गुप्ता ने संशोधन आवेदन पर जोर देते हुए प्रस्तुत किया कि दिनांक 15.1.2025 के आदेश के माध्यम से, प्रकरण को मध्यस्थता और सुलह केंद्र को भेजा गया था और रजिस्ट्रार एचसीएमसीसी की रिपोर्ट 10.4.2025 को प्रस्तुत की गई थी और प्रकरण को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करते हुए, न्यायालय ने याचिकाकर्तागण के पक्ष में अंतरिम राहत दी है "सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक, उपर्युक्त प्रकरण में याचिकाकर्तागण के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

7. उन्होंने प्रस्तुत किया कि विवेचना अधिकारी उक्त आदेश के प्रति पूरी तरह से सचेत थे और मनमाने तरीके से 6.2.2025 को याचिकाकर्तागण को बीएनएसएस की धारा 179 के तहत नोटिस दिया था। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में निष्पक्ष विवेचना की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि विवेचना अधिकारी निश्चित रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। हालांकि, हम संबंधित डीसीपी को प्रकरण की निष्पक्ष, निष्पक्ष विवेचना करने का निर्देश देते हैं और

विवेचना की वर्तमान स्थिति को डीसीपी के रैंक से नीचे के हलफनामे के माध्यम से निर्धारित अगली तारीख पर अवगत कराया जाए।

8. इस प्रकरण को शीर्ष दस प्रकरण में शीर्ष 26.5.2025 में सूचीबद्ध करें।

9. अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, बढ़ाया जाता है।”

5. इस बीच विवेचना अधिकारी ने विवेचना शुरू कर दी थी और विवेचना के दौरान निष्कर्ष निकाला था कि डीपी अधिनियम की धारा 3/4 के तहत कोई प्रकरण नहीं बनता है। हालांकि, उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि प्रकरण की विवेचना बीएनएस की धारा 69 के तहत भी की जानी थी। याचिकाकर्तागण ने 16.04.2025 को रिट याचिका में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया था। संशोधन आवेदन को 28.04.2025 को ही अनुमति दे दी गई थी और संशोधित रिट याचिका की एक प्रति 06.08.2025 को न्यायालय के समक्ष रखी गई थी। विवेचना के रिकॉर्ड पर लाने के संबंध में, जिसके कारण याचिकाकर्तागण पर बीएनएस की धारा 69 के तहत भी आरोप लगाया गया था, विद्वान एजीए द्वारा 06.09.2025 को एक हलफनामा दायर किया गया था। संशोधन की अनुमति दिए जाने के बाद, रिट याचिका अब 12.12.2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को चुनौती दे रही थी, जिसने 2024 के मुकदमा अपराध संख्या 566 को जन्म दिया था और विवेचना बी.एन.एस. की धारा 69, 352, 351(2) के तहत हो रही थी। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से अपनी दलीलें प्रस्तुत करते हुए कहा है कि बीएनएस की धारा 69 के तहत कोई प्रकरण नहीं बनाया गया था। अपनी दलीलें देते समय, उन्होंने न्यायालय को बीएनएस की धारा 69 पढ़कर सुनाई।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि बीएनएस की धारा 69 के तहत अपराध करने के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक थे: -

(i) यदि किसी पुरुष ने किसी महिला के साथ संभोग किया और

(ii) संभोग पुरुष द्वारा अपनाए गए एक निश्चित धोखेबाज साधनों का परिणाम था या शादी करने के किसी भी इरादे के बिना महिला से शादी करने के इस तरह के वादे का परिणाम था;

(iii) बी.एन.एस. की धारा 69 में ही, धोखेबाज साधनों को इस प्रकार समझाया गया है कि (क) किसी पुरुष द्वारा किसी महिला के साथ संभोग करने के लिए रोजगार या पदोन्नति का झूठा वादा करके संभोग करने के लिए प्रलोभन या (ख) झूठा वादा करने के बाद संभोग करना, जिसमें भविष्य में उस विशेष महिला से उसकी पहचान को छिपाकर उससे विवाह करने का झूठा वादा भी शामिल होगा।

6. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि हम बीएनएस की धारा 69 का अध्ययन करते हैं, तो एकमात्र अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अपराध तब किया जाएगा जब कोई पुरुष किसी महिला को या तो शादी का झूठा वादा करके संभोग करने के लिए मनाने में सक्षम है, जिसे भविष्य की तारीख में होना था या यदि वह किसी महिला को इस हद तक धोखा देकर संभोग करने के लिए प्रेरित करता है कि वह विश्वास है कि वह उसे रोजगार देगा या उसे नौकरी में पदोन्नत करने में मदद करेगा। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि शादी करने के झूठे वादे में ऐसी स्थिति शामिल नहीं होगी जहां पुरुष और महिला स्वेच्छा से यौन संबंध बनाते हैं, जब वे ईमानदारी से मानते हैं कि वे एक अच्छे और स्वस्थ रिश्ते में थे। वह प्रस्तुत करता है कि यदि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक रिश्ते में दरार आ जाती है तो बीएनएस की धारा 69 की सामग्री नहीं होगी और बीएनएस की धारा 69 के तहत माना गया अपराध नहीं होगा। वह प्रस्तुत करता है कि विचाराधीन धारा छल को दंडित करती है न कि निराशा को। इस प्रकरण में, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से ही पता चलता है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 4 के साथ संबंध बनाने के बाद जब वे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर में एलएलएम कोर्स में शामिल हुए, तो वे पहले दोस्त बन गए और उसके बाद उनके शादी करने के सभी इरादे थे। याचिकाकर्ता संख्या 1 जो कुछ भी कर रहा था, उसमें झूठे वादे का कोई तत्व नहीं था। निश्चित रूप से, प्रत्यर्थी संख्या 4 को यह विश्वास करने के लिए धोखा देने के लिए कोई कपटपूर्ण साधन नहीं अपनाया गया था कि याचिकाकर्ता संख्या 1 उसे नौकरी दिलाने में मदद करेगा या उसे पदोन्नत करेगा। निश्चित रूप से शादी करने का कोई झूठा वादा नहीं था। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रत्यर्थी संख्या 4 के बीच सगाई जून, 2023 में हुई थी और विवाह 12.11.2024 को होना था। हालांकि, अचानक जब याचिकाकर्तागण के कहने पर 04.11.2024 को विवाह रद्द कर दिया गया, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि शुरू में प्रथम सूचना रिपोर्ट में शादी को रद्द करने के किसी

भी कारण का खुलासा नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट शादी को रद्द करने के कारणों के बारे में बिल्कुल चुप थी। इस तथ्य को स्थापित करने के लिए कि याचिकाकर्ता विवाह के बारे में ईमानदार थे और विवाह संपन्न करने के संबंध में याचिकाकर्ता संख्या 1 की ओर से कोई झूठा वादा नहीं किया गया था, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका के रिकॉर्ड के माध्यम से न्यायालय को लिया था, जिसमें यह कहा गया था कि निमंत्रण कार्ड मुद्रित किए गए थे और याचिकाकर्तागण के रिश्तेदारों को जारी किए गए थे। इसके अलावा, चूंकि शादी मेरठ में होनी थी, इसलिए याचिकाकर्तागण ने तस्वीरें लेने के लिए एक फोटोग्राफर की भी व्यवस्था की थी। रिसेप्शन प्रयागराज में होटल यात्री में आयोजित किया जाना था, इसलिए होटल यात्री को भी याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 के खाते से 3,00,000/- रुपये देकर बुक किया गया था। साथ ही मेरठ में होने वाली शादी के लिए 27.09.2024 को होटल सफायर गैंड को 2,50,000/- रुपये दिए गए। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्तागण और उनके रिश्तेदारों को शादी में शामिल होने के लिए यात्रा योजना और टिकट उपलब्ध कराए गए थे। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विवाह के उद्देश्य से विभिन्न कपड़े आदि भी सिले गए थे। निश्चित रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं था कि समाचार पत्रों में विभिन्न समाचार रिपोर्टों के कारण शादी को रद्द कर दिया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 4 के पिता को नौकरी से निलंबित कर दिया गया था। यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 के पिता ने याचिकाकर्तागण को कई धमकी भरे टेलीफोन कॉल किए थे और याचिकाकर्तागण को धमकी देने वाले याचिकाकर्तागण के घर भी आए थे। प्रत्यर्थी संख्या 4 और उसके पिता की पुलिस को कई शिकायतों के कारण पुलिस द्वारा याचिकाकर्तागण को विभिन्न नोटिस भेजे गए थे। इसके कारण याचिकाकर्तागण ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ 2024 की आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 22191 (नीलेश रामचंदानी और 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) के रूप में एक रिट याचिका दायर की थी:

“इसलिए, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपया निम्नलिखित पर कृपा करे:

क) प्रत्यर्थी संख्या 3 - एसएचओ, महिला थाना, सेक्टर 39, नोएडा, आयुक्तालय गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी दिनांक 12.11.2024 (अनुलग्नक संख्या 14), 21.11.2024 (अनुलग्नक संख्या 15), और 22.11.2024 (अनुलग्नक संख्या 16) द्वारा जारी किए गए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना

(अनुलग्नक संख्या 17)।

ख) प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दायर दिनांक 05.11.2024 की शिकायत के संबंध में याचिकाकर्तागण के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम/उपाय न करने का आदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें। (अनुलग्नक संख्या 17)

ग) प्रत्यर्थी संख्या 4 (अनुलग्नक संख्या 17) द्वारा दायर दिनांक 05.11.2024 की शिकायत के अनुसरण में एक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रकरण को इस माननीय उच्च न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र को भेजने के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें

वैकल्पिक रूप से

घ) प्रत्यर्थीगण को दिनांक 05.11.2024 की शिकायत के अनुसार याचिकाकर्तागण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रारंभिक विवेचना/मध्यस्थता में भाग लेने की अनुमति देने के लिए संबंधित प्रत्यर्थीगण को एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना। (अनुलग्नक संख्या 17)

ड) कोई अन्य आदेश या निर्देश पारित करना जिसे यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में न्यायोचित और उचित समझे।

7. हालांकि, रिट याचिका को समय से पहले होने के कारण खारिज कर दिया गया था और न्यायालय द्वारा इसे वापस लेने की अनुमति दी गई थी। जब 12.12.2024 को एक पूर्ण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, तो तत्काल रिट याचिका दायर की गई और जैसा कि पहले फैसले में कहा गया है कि जब प्रकरण की विवेचना बीएनएस की धारा 69 के तहत भी की जा रही थी, तो रिट याचिका में भी संशोधन किया गया था। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रभावी रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट को चुनौती दी है और कहा है कि बीएनएस की धारा 69 के तहत कोई प्रकरण नहीं बनाया गया था।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

(I) वह प्रस्तुत करता है कि वर्तमान प्रकरण में लगाए गए आरोप पूरी तरह से प्रत्यर्थी संख्या 4 के दावे पर निर्भर करते हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने शादी के झूठे बहाने से उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा कोई

झूठा वादा नहीं किया गया था जिसे केवल संभोग करने का वादा कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर पहली सूचना रिपोर्ट का अध्ययन किया जाता है तो यह निश्चित रूप से किसी भी यौन संबंध के बारे में नहीं बोलती है। हालांकि, भले ही प्रत्यर्थी संख्या 4 के बाद के बयान जो बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज किए गए थे, वे सभी इस आशय के थे कि पक्षों के बीच लंबे समय तक निरंतर शारीरिक संबंध थे और यह संबंध इस तथ्य के कारण जारी था कि प्रत्यर्थी संख्या 4 ने भी याचिकाकर्ता संख्या 1 को पसंद किया था।

(II) याचिकाकर्ता संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 4 को केवल शारीरिक सुख के लिए लुभाया नहीं था और फिर गायब हो गया था। यह रिश्ता वर्ष 2020 में शुरू हुई अवधि के लिए जारी रहा। प्रत्यर्थी संख्या 4 के बयानों से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रत्यर्थी संख्या 4 दोनों करीब रहे थे और भावनात्मक रूप से शामिल थे और इस प्रकार यदि निरंतर संबंध के दौरान कोई शारीरिक अंतरंगता हुई थी और इसे पूर्वव्यापी रूप से एक झूठे वादे के आधार पर शुरू होने के रूप में चिह्नित नहीं किया जा सकता है।

(III) केवल इसलिए कि विवाह संबंध टूटने के कारण नहीं हुआ, भले ही वह याचिकाकर्ता संख्या 1 की ओर से हो, यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि कोई शारीरिक संबंध था तो यह झूठे वादे के आधार पर था।

(IV) याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जब पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रत्यर्थी संख्या 4 ने शारीरिक संबंध होने के बारे में एक शब्द भी उल्लेख नहीं किया था और उसके बाद उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिए थे, तो इसे भी एक ऐसी स्थिति के रूप में लिया जाएगा जहां वह याचिकाकर्तागण को फंसाने की झूठी कोशिश कर रही थी।

(V) याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि यद्यपि याचिकाकर्ता को शारीरिक संबंध के तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया था, भले ही यह प्रत्यर्थी संख्या 4 के बयान के अनुसार हुआ हो, फिर भी बीएनएस की धारा 69 की सामग्री नहीं बनाई गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 4 के बयानों के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि यदि पक्षों के बीच सहमति से और स्वेच्छा से शारीरिक संबंध थे, तो प्रत्यर्थी संख्या 4 याचिकाकर्ता संख्या 1 के साथ उतना ही संबंध रखता था जितना कि याचिकाकर्ता संख्या 1 उसके साथ था। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने समर्थन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है। 2025 की आपराधिक अपील संख्या 5001 में पारित किया गया और प्रस्तुत किया कि यदि

सहमति और स्वैच्छिक संबंध थे और याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रत्यर्थी संख्या 4 के कृत्यों से पता चलता है कि वे एक ऐसे रिश्ते में थे जो किसी भी जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गलत बयानी से रहित था, तो निश्चित रूप से बीएनएस की धारा 69 के तहत कोई अपराध नहीं किया गया था। इस संदर्भ में याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भी भरोसा किया है— विश्वज्योति चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य; एसएलपी (आपराधिक) संख्या 4621/2024, रजनीश सिंह @ सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य; कुणाल चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य; प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य; (2019) 9 एससीसी 608; प्रशांत बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य; एआईआर 2025 एससी 33; मनीष यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; आपराधिक अपील संख्या 333/2025, बी.एन. जॉन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2025 आईएनएससी 4 तथा प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। यह प्रस्तुत किया गया कि जब पक्षकारों (अर्थात् याचिकाकर्ता संख्या-1 एवं प्रत्यर्थी संख्या-4) के मध्य संबंध विद्यमान था, तब मिथ्या वचन/छल का कोई तत्व नहीं बनता। अतः प्रार्थना की गई कि रिट याचिका स्वीकार की जाए तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द किया जाए।

8. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि यदि सभी निर्णयों का अवलोकन किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायिक अपेक्षा यह है कि बीएनएस की धारा 69 छल को दंडित करती है न कि निराशा को। न्यायालय को आकलन करना होगा

(क) क्या विवाह का वादा शुरू से ही झूठा था

(ख) क्या एफआईआर के समय से प्रतिशोध का पता चलता है

(ग) क्या वस्तुनिष्ठ साक्ष्य चैट, संदेश, फोटो कथित पीड़ित के दावे का समर्थन करते हैं।

(घ) क्या पक्ष वयस्क हैं और सहमति देने में सक्षम हैं

(ङ) क्या हिरासत में पूछताछ वास्तव में आवश्यक है (इस प्रकार के प्रकरण में, यह शायद ही कभी होता है)

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने अंकित हुकुमचंद मालवीय बनाम महाराष्ट्र राज्य 2025 एससीसी ऑनलाइन बॉम 734 पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि हर रोमांटिक विफलता को धोखे के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, दीपक बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एमपी 2689 पर भरोसा करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय

ने चेतावनी दी और कहा कि आपराधिक विधि सहमति देने वाले वयस्कों के बीच आरोपण का उपकरण नहीं बन सकता है। इसी तरह, **यशवंत निर्मलकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2025 एससीसी ऑनलाइन 3712** में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा करते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि वादा शुरू से ही झूठा था, अन्यथा, अपराध नहीं होता। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार धोखे और निराशा के बीच की सीमा को संरक्षित किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आपराधिक विधि धोखाधड़ी के खिलाफ एक ढाल बना रहे न कि व्यक्तिगत विवाद को निपटाने के लिए एक हथियार।

9. हालांकि, प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवम शुक्ला और श्री अनिकेत गुप्ता और श्री अमित सिन्हा, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि प्रकरण की पहले विवेचना की जानी थी और उसके बाद विवेचना अधिकारी द्वारा केवल एक निश्चित निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि क्या बीएनएस की धारा 69 के तहत कोई प्रकरण बनाया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रकरण असफल रिश्ते का नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रकरण था जहां याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 4 के परिवार से दहेज लेने के लिए शादी का झूठा वादा किया था। प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने **मेसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2021) 19 एससीसी 409** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर, प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने भी **नफीसा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जो **2023 एससीसी ऑनलाइन एएलएल 17** में प्रतिवेदित था। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में **सीआरएम(एम) संख्या 216/2025** में पारित **शकीर-उल-हसन बनाम जम्मू कश्मीर एवं अन्य**, जो जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय, श्रीनगर द्वारा पारित किया गया है, के निर्णय पर भी भरोसा किया।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि जहां तक बीएनएस की धारा 69 का संबंध है, निश्चित रूप से अपराध तभी किया जाएगा जब किसी पुरुष द्वारा विवाह के संबंध में किसी महिला से झूठा वादा किया गया हो और उसके बाद उसने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए हों। महिला उस आदमी पर इस हद तक विश्वास करेगी कि वास्तव में, वह इस तथ्य के बावजूद शादी कर लेगा कि उसका वास्तव में उससे शादी करने का कोई

इरादा नहीं था। इस प्रकरण में, हम प्रथम सूचना रिपोर्ट को पढ़ने से ही पाते हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रत्यर्थी संख्या 4 ने एक ही कॉलेज से एलएलबी कोर्स किया था। एलएलबी कोर्स करने के बाद, उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर में दाखिला लिया जहां से उन्होंने एलएलएम कोर्स किया। ऐसा नहीं था कि प्रत्यर्थी संख्या 4 को याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा शारीरिक संबंध बनाने के लिए लालच दिया गया था क्योंकि वह भविष्य में शादी के झूठे वादे कर रहा था, बल्कि हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रत्यर्थी संख्या 4 एक-दूसरे को इस हद तक पसंद करने लगे थे कि वे बहुत अंतरंग हो गए थे और सहमति और स्वेच्छा से शारीरिक संबंध में थे। उक्त शारीरिक संबंध इस हद तक जारी रहा कि मई, 2023 के महीने में याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रत्यर्थी संख्या 4 की भी सगाई हो गई थी। याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रत्यर्थी संख्या 4 के बीच न केवल उपरोक्त संबंध थे, बल्कि याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 ने भी प्रत्यर्थी संख्या 4 के परिवार से मुलाकात की थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट के संस्करण के अनुसार ही प्रत्यर्थी संख्या 4 के माता-पिता याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रत्यर्थी संख्या 4 की शादी के लिए सहमत हुए थे और उन्होंने याचिकाकर्ता संख्या 4 को भी दिया था। 1 बढ़ते रिश्ते की मान्यता में एक चांदी का सिक्का। कल्पना के किसी भी हिस्से से यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 को जबरन या धोखेबाज शारीरिक संबंध में प्रवेश करने के लिए कोई लालच या गलत बयानी की गई थी। हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 के प्रत्यर्थी संख्या 4 को भी पसंद आ रहा था। हम, रिकॉर्ड और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से, पाते हैं कि विवाह की तारीख भी तय की गई थी और विवाह के संपन्न होने की व्यवस्था की गई थी। हालाँकि, जिस रिश्ते में याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रत्यर्थी संख्या 4 शामिल हो गए थे, वह खट्टा हो गया था और अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया था।

11. हमारा निश्चित रूप से यह विचार है कि बीएनएस की धारा 69 छल को दंडित करती है न कि निराशा को। वर्तमान प्रकरण में, हम पाते हैं कि पक्षकारगण के बीच शादी करने के लिए एक समझौता था और वास्तव में याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 से कोई एकतरफा या धोखेबाज वादा नहीं किया गया था कि वह निकट भविष्य में उससे शादी करेगा। इसलिए पक्षकारगण के बीच शादी करने का समझौता बहुत अधिक अस्तित्व में था। दोनों तरफ से कोई झूठा वादा नहीं किया गया था। हमारा यह भी विचार है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का समय ऐसा था जो प्रत्यर्थी संख्या 4 के अनुकूल नहीं था, यह ऐसे समय में दर्ज किया गया था जब याचिकाकर्ता संख्या 1 ने सोचा था कि विवाह किसी न किसी कारण से संभव नहीं है। हमारा यह भी विचार है कि रिट

याचिका में जो सबूत प्रदान किए गए हैं, वे निश्चित रूप से इस हद तक थे कि याचिकाकर्ता संख्या 1 की ओर से शादी या धोखेबाज साधनों का कोई झूठा वादा नहीं था।

12. यह पाए जाने के बाद कि शादी करने का कोई झूठा वादा नहीं किया गया था या कोई धोखेबाज साधन अपनाए गए थे, जिसके आधार पर संबंध उस हद तक चले गए थे जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा उल्लेख किया गया था, हमारा विचार है कि बीएनएस की धारा 69 के तहत अपराध का गठन करने वाला कोई भी तत्व नहीं बनाया गया था। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि बीएनएस की धारा 351 (2) और 352 जैसी दो अन्य धाराएं हैं जिनके तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। **लवली सल्होत्रा एवं अन्य बनाम राज्य (एनसीटी/दिल्ली) और एक अन्य (2018) 12 एससीसी 391** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट को निश्चित रूप से आंशिक रूप से रद्द किया जा सकता है।

13. अतः हम इस सुविचारित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, जहाँ तक वह बी.एन.एस. की धारा 69 के अंतर्गत जांच से संबंधित है, रद्द की जाती है। फलस्वरूप, मुकदमा अपराध संख्या 566 वर्ष 2024, जो धारा 352, 351(2), 69 बी.एन.एस. के अंतर्गत पंजीकृत था, उसमें धारा 69 के अंतर्गत दर्ज भाग को निरस्त किया जाता है। हालांकि, धारा 351(2) एवं 352 बी.एन.एस. के अंतर्गत विवेचना कार्यवाही यथावत जारी रहेगी।”

14. हालांकि, चूंकि विवेचना के दौरान याचिकाकर्तागण को उनके खिलाफ की जा रही किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचाने के लिए एक अंतरिम आदेश था, इसलिए हम प्रदान करते हैं कि विवेचना अब बीएनएस की धारा 351 (2), 352 के तहत चल सकती है। हालांकि, याचिकाकर्तागण को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है।

15. रिट याचिका को आंशिक रूप से **स्वीकृत** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा)

29 जनवरी, 2026

एम.एस. अंसारी